भारतीय विज्ञान सम्मेलन के 93वें अधिवेशन में प्रधानमंत्री का संबोधन

3 जनवरी, 2006
हैदराबाद

आज, यहां हैदराबाद में भारतीय विज्ञान सम्मेलन के 93वें अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है । सबसे पहले मैं प्रो. एम.सी. पुरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनकी, भारत में विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में, हमारे देश के सर्वाधिक निन्दनीय और कायर दुश्मनों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी । डॉ. पुरी ज्ञान के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ थे । उन्होंने विज्ञान और शिक्षा को समर्पित शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया । कोई भी सभ्य समाज उनकी हत्या जैसे निदंनीय कृत्य को माफ नहीं कर सकता ।

यह निश्चय ही भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सफलता का और ज्ञानशक्ति के रूप में हमारे आविर्भाव का प्रतीक है कि आतंकवादी हमारे बौद्धिक वर्ग के प्रतीकों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बना रहे हैं । मुझे विश्वास है कि हमारे देश के सभी बुद्धिजीवी एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे और भारत को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक मानवीय और आधुनिक राष्ट्र, एक ज्ञानशक्ति । भारत के लोगों की इस प्रतिज्ञा को धरती की कोई भी ताकत कमजोर नहीं बना सकती ।

देवियो और सज्जनो,

मुझे खुशी है कि आपने इस अधिवेशन के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय परिसर को चुना है क्योंकि इस वर्ष हम प्रायद्वीप में आधुनिक कृषि महाविद्यालयों की स्थापना का शतक पूरा करने जा रहे हैं । भारत में भूमि -संबंधी परिवर्तनों में हमारे कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस अधिवेशन का मुख्य विषय एकीकृत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका है । मैं समझता हूँ कि इस विषय पर आप लगभग तीन दशकों के पश्चात् चर्चा कर रहे हैं । पिछली बार इस विषय पर 1976 में इंदिराजी ने आंध्र प्रदेश में ही, जो चावल का सबसे बढ़ा उत्पादक है, एक विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया था । यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में कृषि क्षेत्र के सबसे खराब दौर के एक दशक बाद का समय था । सातवें दशक के मध्य में कहा जाता था कि भारत खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। किंतु 1976 तक, हरित क्रांति से देश के कई भागों में स्थिति बदल चुकी थी ।

हमारे देश के वैज्ञानिकों, किसानों सामुदायिक विकास कार्यकर्त्ताओं और सहायक कार्मिकों ने भारत को खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भरता से मुक्त कराने के लिए एकजुट होकर कार्य किया । भारतीय विज्ञान सम्मेलन महान आंध्र पुत्र डॉ. नयुदम्मा, डॉ. एम.एस.

स्वामीनाथन, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, और ऐसे अन्य वैज्ञानिकों की प्रशंसा करता है जिन्होंने विज्ञान के लाभों को कृषि से जोड़ा है । डॉ. नयुदम्मा उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने वैज्ञानिकों से एकीकृत ग्रामीण विकास में पहल करने और सहायता करने का आग्रह किया । उन्होंने ही, यहां आंध्र प्रदेश में, करीमनगर परियोजना का सूत्रपात किया जिसके फलस्वरूप वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद् सहायक कार्मिकों और सामुदायिक विकास कार्यकर्त्ताओं ने एक साथ मिलकर कार्य किया । इस अनुभव से हमने क्या सीखा और इस प्रयास को आगे कैसे ले जाया जाए यह एक रूचिकर विषय है ।

आज तीस वर्ष के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि भारतीय किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान से वास्तव में काफी लाभ हुआ है । हालांकि प्रगति के बावजूद शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की विकास संबंधी खाई को पाटने, ग्रामीणों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि और ग्रामीण कृषीतर अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने; गांवों में आधारभूत संरचना सुधारने और अंततः भारत और इंडिया के बीच की तथाकथित दूरी को मिटाने की चुनौती अभी विद्यमान है । प्रथम हरित क्रांति से प्रवर्तित प्रौद्योगिकी और नीतियां अपना काम पूरा कर चुकी हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है खाद्येतर फसलों, उद्यान कृषि, पौधों की नई किस्मों के क्षेत्र में अब आवश्यकता है दूसरी हरित क्रांति की ।

आज जब मैं देखता हूँ कि कृषि संबंधी विकास में ठहराव -सा आ गया है तो मैं यह महसूस करता हूँ कि ऐसे अनुसंधान कार्यों पर पुनः बल देने की आवश्यकता है जिनसे उत्पादकता में वृद्धि हो । हमें ऐसे अनुसंधान कार्यों पर अधिक जोर देना होगा जो निविष्ट सामग्री के बेहतर उपयोग में वृद्धि करें, खेतों में प्रबंध व्यवस्था में सुधार करें, कटाई के बाद भंडारण, परिवहन और संसाधन में बेहतर प्रबंध -प्रौद्योगिकी द्वारा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करें और अंततः उपज और किसानों के स्तर पर मूल्यों में वृद्धि करें ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हों कि कृषि पर निर्भर हमारे देशवासी प्रौद्योगिकी और ज्ञान के इस युग में पीछे न छूट जाएं।

भारत में वन संरक्षण और प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और जड़ी -बूटियों तथा पौधों की उपयोगिता में विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में वृद्धि की आवश्यकता है । हमें उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और स्थानीय जानकारी के सुव्यवस्थित सम्मिश्रण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई -नई जानकारियों के लाभ सभी को मिल सकें ।

वर्ष 1976 में हुए विज्ञान सम्मेलन में इंदिरा जी ने कहा था -

" भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और आने वाले कई वर्षों में वहीं रहती रहेगी । इस संबंध में मैं यही कहूँगी कि हम उन्हें वहां से उखाड़ना भी नहीं चाहते । संपूर्ण विश्व में आधुनिकीकरण से सुख-साधनों में वृद्धि हुई है, और जीवन की रफ्तार में तेजी आई है ।

इससे जटिलताएं भी उत्पन्न नहीं हुई ? हमें ग्रामीण जीवन को इस तरह से समृद्ध करना होगा कि गांवों से शहर की ओर जाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए । उन देशों में किए गए उपाय, जहां खेतिहर जनसमुदाय कार्यबल का एक छोटा सा ही हिस्सा है, हमारे देश में लागू नहीं हो सकते । "

इंदिरा जी के ये विद्वतापूर्ण विचार आज भी सटीक हैं । ग्रामीण भारत के लिए हमारी कार्यनीति गांवों के जीवन में सुधार करने वाली तथा सुगम और उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित होनी चाहिए ताकि लोग अपने पूर्वजों की धरती पर रहते हुए भी साधन -सम्पन्न और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकें । यदि वैज्ञानिक अधिक समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।

एक अवसर पर महात्मा गांधी जी ने कहा था - " गांवों के विनाश का अर्थ भारत का विनाश है ।" तब शायद वह ओलिवर गोल्डस्मिथ के विचारों को दोहरा रहे थे, जिन्होंने लिखा है-

" सबल कृषक वर्ग से ही, होगी देश की उन्नति,
जो गिरा एक बार यह तो, होगी वहीं पर इति"

देवियो और सज्जनो,

ग्रामीण भारत की मेरी संकल्पना में एक ऐसा भारत है जहां आधुनिक कृषिक औद्योगिक और सेवा अर्थव्यवस्था साथ- साथ फलें -फूलें, जहां लोग सुख -साधन सम्पन्न गांवों में रहें और अपने कार्यस्थल तक, सरलता से आ - जा सकें चाहे वह खेती से जुड़ा काम हो या खेती से हटकर । इस स्वप्न को साकार करने में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफी अधिक सहायता कर सकते हैं । इसके लिए ग्रामीणों की आय में वृद्धि करनी होगी, गांवों की अवसंरचना में सुधार करना होगा, गांवों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे ।

हमारी सरकार ने इनमें से हर क्षेत्र में अनेक प्रयास किए हैं । हमने 'भारत - निर्माण' कार्यक्रम आरंभ किया है, जो गांवों की अवसंरचना, जैसे - गांवों में सड़कों, विद्युत, आवास, दूरसंचार और सिंचाई, में सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है । हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान आरंभ किया है और गांवों में शिक्षा तथा स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधि में वृद्धि की है । हमने ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिनियमित किया और किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराया है । ये सभी प्रयास ग्रामीण भारत को नवीन अवसर प्रदान करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं ।

आपके सामने अब चुनौती है उत्कृष्ट कोटि के विज्ञान पर कार्य करने की, विश्व स्तरीय अनुसंधान करने की और साथ ही ग्रामीण भारत में विकास और रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की । आपमें से जो व्यक्ति इस चुनौती का सामना करने में सफल रहेंगे उन्हें ही सही मायनों में आधुनिक भारत का निर्माता माना जाएगा ।

देवियो और सज्जनो,

अब मैं उन तीन चुनौतियों पर चर्चा करूँगा जिन पर कार्य करके आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ग्रामीण भारत के विकास की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं । सबसे पहले, हमें कृषि उत्पादकता अर्थात - भूमि, श्रमिक, बीज और पौधों तथा उत्पाद के अन्य कारकों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा । मेरी नज़र में यही द्वितीय हरित - क्रांति होगी । दूसरे, हमें ऊर्जा और जल के लिए सुलभ और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा । और तीसरे, हमें खेती और खेती से इतर व्यवसायों में ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास करना होगा जिनमें श्रमिकों को काम भी मिलें और वे फलोत्पादक और संगत भी हों ।

द्वितीय हरित क्रांति

राष्ट्रीय कृषक आयोग ने "कृषिक नवीकरण" के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है जो द्वितीय हरित क्रांति की शुरूआत हो सकता है । इसमें प्रस्तावित पांच घटक निम्नानुसार हैं - (क) मृदा के भौतिक, रसायनिक, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान पर एक साथ ध्यान देकर मृदा की गुणता में वृद्धि;

(ख) जल संचयन, जल संरक्षण और लंबे समय तक और उचित रूप से जल का उपयोग; (ग) सुलभ ऋण और फसल तथा जीवन बीमा संबंधी सुधारों की उपलब्धता ; (घ) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा; (ड.) उत्पाद के विपणन के लिए बेहतर अवसर, अवसरंचना और विनियम ।

इस समूह में मैं दो और घटक जोड़ना चाहूँगाः (च) बीजों के सुधार और जड़ी -बूटियों एवं अन्य पौधों को उपयोग मे लाने के लिए विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग; और, (छ) पशुधन और मुर्गी पालन के क्षेत्रों में उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए पशु पालन- में विज्ञान का अनुप्रयोग । इन सातों क्षेत्रों के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफी सहायक हो सकते है । या फिर यूँ कहें कि कृषि विश्वविद्यालय इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में काफी सहायक हो सकते हैं ।

हम जिन भी प्रौद्योगिकियों का विकास करें वे आर्थिक रूप से सुलभ और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए संगत होनी चाहिए, विशेष रूप से सूखा प्रवर क्षेत्रों में । पहली हरित क्रांति में दो खामियां बताई गईं - एक तो यह कि उससे शुष्क भूमि कृषि में लाभ नहीं हुआ और दूसरी यह कि वह सर्वदर्शी नहीं थी और उससे केवल बड़े खेतों और बड़े किसानों को ही

लाभ हुआ । यद्यपि इस बात के प्रमाण हैं कि यह सर्वथा सत्य नहीं है । फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि द्वितीय हरित क्रांति शुष्क भूमि कृषि और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हो ।

द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए हमें अपने कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को नया रूप देना होगा । हमें इन संस्थानों को पुनः सक्रिय करना होगा । हमें इन संस्थानों के शैक्षिक परिणामों और कृषि समाज और अर्थव्यवस्था में इनकी उपयोगिता में सुधार करना होगा ।

सभी उन्नत कृषि अर्थव्यवस्थाएं ज्ञान -आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं। हमें अपने किसानों को अधिक जानकारी उपलब्ध करानी होगी ताकि वे नई प्रौद्योगिकियों का बेहतर उपयोग कर सकें । हमारे किसानों की सूचना -संबंधी आवश्यकताएं बहुमुखी हैं, वे सिर्फ प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है। उन्हें व्यापार के रूप में कृषि से संबंधित जानकारी, कृषि पद्धतियों, नीति संबंधी प्रयासों, अन्य किसानों को उपलब्ध बेहतर तरीकों और बाज़ार आसूचना से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है । अतः सही समय पर सूचना उपलब्ध कराना कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक है ।

इन सभी मांगों और किसानों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए हमें अपनी सहायक सेवाओं को और भी साधन सम्पन्न बनाना होगा । पिछले दो दशकों में सहायक सेवाएं निष्क्रिय -सी हो गई हैं । हमें ऐसे नए तरीकें खोजने होंगे जिनसे कृषि स्नातकों के कौशल का उपयोग बेहतर सहायक कार्य के लिए किया जा सके । किसानों और अनुसंधानकर्त्ताओं के बीच के प्रत्यक्ष अवरोधों को दूर करने के लिए संचार के नए साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है । मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् लगभग 200 कृषि विज्ञान केंद्रों को इलेक्ट्रॉनिक संपर्क प्रदान करने और उन्हें हमारे किसानों के लिए सूचना प्राप्ति केंद्र बनाने का प्रयास कर रहा है । मैं समझता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रत्येक जिले में ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना होगा । उन्हें वैज्ञानिकों, सहायक कार्मिकों और किसानों को एक दूसरे के निकट लाकर संभावित और वास्तविक कृषि उपज के बीच के अंतर को दूर करना होगा ।

ऊर्जा और जल

भूमि के समान ही जल और ऊर्जा भी दुर्लभ संसाधन हैं । कारक उत्पादकता में वृद्धि करके और इन संसाधनों की उपयोगिता को संरक्षित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनकी आपूर्ति में सहायक हो सकते हैं । पश्चिमी देशों ने जल, बायोमास (जैव पदार्थ), सौर व अन्य संगत ऊर्जा स्रोतों पर अनुसंधान में ज्यादा निवेश नहीं किया है क्योंकि उन्हें उस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता जो हमारे सामने हैं । सौर-ऊर्जा और बायोमास वे क्षेत्र हैं जिनमें अनुसंधान और विकास में भारतीय वैज्ञानिकों को सबसे आगे होना चाहिए । मैं समझता हूँ कि ऐसे अनुसंधान कार्यों से हम संसाधनों के लाभकारी उपयोग, बेहतर उत्पादकता

और आसानी से प्राप्त हो पाने वाली अवसंरचना के विकास में योगदान दे सकते हैं । हमारी सरकार जल और ऊर्जा से संबद्ध उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विश्वस्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी ।

हमें ऊर्जा और जल की व्यवस्था में विज्ञान आधारित समाधानों की अत्यावश्यकता है, विशेष रूप से वर्षा -सिंचित क्षेत्रों में भूमि जल के उपयोग के साथ -साथ हमें अनिवार्य रूप से वर्षा जल का संचयन करना और जलस्तर को पुनः पूरित करना होगा । हमारी सरकार ने जलसंभरण (वाटरशैड) विकास और भूमिगत जल की पुनःपूर्ति के लिए अनेक प्रयास किए हैं । देश के कई क्षेत्रों में कुछ नदियों को परस्पर जोड़ने से भूमिगत जल पर निर्भरता और भू -जल की पुनः पूर्ति को कम किया जा सकता है । मैं चाहता हूँ कि नदियों के जल के पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखते हुए और आर्थिक रूप से सुलभ तरीके से उपयोग पर सुविज्ञ चर्चा हो।

मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में इन मुद्दों के लिए निर्धारित सत्र में हमें ऐसे सुझाव प्राप्त होगे कि देश की 100 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचाए बिना और कम से कम लोगों को विस्थापित करके किस प्रकार सींचा जा सकता है ।

रोजगार उत्पन्न करना और खेती से इतर कार्यकलाप

देवियो और सज्जनो,

हमारी सरकारी नीति भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के अनुसार होनी चाहिए । आज राष्ट्रीय आय में कृषि से होने वाली आय का अंश तो कम होता जा रहा है किंतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कोई कमी नहीं हो रही है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाली आती जा रही है और लोगों को जबरन शहरी क्षेत्रों का रूख करना पड़ रहा है । इस प्रवृत्ति का एक ही युक्तियुक्त समाधान है और वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और खेती से इतर दोनों क्षेत्रों में फलोत्पादक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं । वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को कृषि और ग्रामीण विनिर्माण कार्यों, दोनों में श्रमोपयोगी प्रौद्योगिकियों का विकास करना होगा ताकि हमारे ग्रामीण भाईयों को उनके निवास स्थान के पास ही रोजगार मिल सके ।

और, इसके लिए बहुमुखी दृष्टिकोण की आवश्यकता है । इसमें निश्चय ही कौशल विकास में निवेश की आवश्यकता होगी । इसमें खेतों पर काम में आने वाली श्रमोपयोगी प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृषि उत्पादों के संसाधन, पैकेजिंग और विपणन में वित्तपोषण की आवश्यकता है । हमें अपने हथकरघा और दस्तकारी उद्योगों का भी आधुनिकीकरण करना होगा ताकि ग्रामीण कारीगर नए बाजारों से जुड़ सकें । मौजूदा शहरों से दूर ऐसी नई कारगर टाउनशिपों का विकास करना होगा जिनमें सभी मूल साधन उपलब्ध हों ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में नए निवेश हो सकें ।

इन सभी से नई प्रौद्योगिकी के विकास के अवसर खुलते हैं । कृषि विश्वविद्यालयों को ऐसी संभावनाओं के लिए बौद्धिक रूप से जागृत होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम व कार्यक्रम तैयार करने चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर और उन्हें अधिकाधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें वहीं रहने को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प ही कहां है ?

ऐसा करने के लिए हमें विकेंद्रित ऊर्जा उत्पादन, विकेंद्रित सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना विकास और शासन तथा व्यापार कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के विकेंद्रीकरण पर ध्यान देना चाहिए । अत्यधिक केंद्रीकरण हमारे देश के विकास पर श्राप के समान रहा है । व्यापार पर तथा वस्तुओं, सेवाओं व लोगों की आवाजाही पर आंतरिक रूकावटों को हटाकर एकल बाजार का निर्माण करते हुए हमें स्थानीय बाजार का विकास भी सुनिश्चित करना होगा ताकि स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय हल ढूंढे जा सके ।

देवियो और सज्जनो,

मैं दिल से चाहता हूँ कि निकट भविष्य में हम ग्रामीण भारत का शीघ्रता से आधुनिकीकरण कर सकें और यह सुनिश्चित करें कि इस विकास का लाभ हमारे देश के कोने -कोने तक पहुँच सके । इसे संभव बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को सरकारी व गैर -सरकारी संगठनों के साथ, स्थानीय निकायों और पणधारी समूहों के साथ मिलकर कार्य करना होगा । मैं आशा करता हूँ कि सम्मेलन में उपस्थित आप सभी लोग हमारी जनता के इन महत्वपूर्ण हितों के लिए कार्य करेंगे । मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी राष्ट्र के गौरव के प्रति समर्पित होकर कार्य करें ।

और अंत में आप सब को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस कार्य में सफलता प्राप्त करें ।

जय हिंद !